सिर मुड़ाते ही ओले पड़े

दिल्ली विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी में खींचतान की खबरें चौंकाने वाली हैं। चौंकाने वाली इसलिए कि दिल्ली की सत्ता संभाले एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और शीर्ष नेतृत्व में टकराव की खबरें सामने आने लगीं। खबरें यहां तक तैर रही हैं कि पार्टी के संस्थापक सदस्य योगेन्द्र यादव को राजनीतिक मामलों की समिति से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। किसी भी राजनीतिक दल में फैसले लेने वाला एक समूह होता है जिसमें समय-समय पर बदलाव होना आम बात है। अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकली आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति से कभी सरोकार नहीं रहा। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सरकारी सेवा छोड़कर राजनीति में कदम रखा तो मनीष सिसोदिया, आशुतोष और आशीष खेतान सक्रिय पत्रकारिता छोड़कर समाज में बदलाव के लिए आगे आए। जाने-माने वकील प्रशांत भूषण और चुनावी राजनीति के विशेषज्ञ समझे जाने वाले योगेंद्र यादव भी आम आदमी की आवाज बुलंद करने के लिए पार्टी के साथ जुड़े। अलग-अलग धाराओं से आने वाले इन तमाम लोगों का मकसद बदरंग होती राजनीति में नए रंग भरना था। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और जाति-धर्म की राजनीति को बदलकर ये लोग योग्य और ईमानदार छवि के लोगों को राजनीति में लाने के पक्षधर थे। सवा साल पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर इन्होंने दिखा दिया कि जनता ऐसे लोगों के समर्थन को तैयार है। कांग्रेस से मिलकर दिल्ली में सरकार बनाने की इनकी रणनीति कारगर भले ना हुई हो लेकिन आम जनता ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास बनाए रखा। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बावजूद पार्टी ने हौसला नहीं खोया और पिछले महीने हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी दलों का सफाया करके ऐतिहासिक जीत हासिल की। पार्टी जब अपने वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही हो, ऐसे समय में शीर्ष नेतृत्व में टकराहट आम आदमी के लिए पीड़ादायक मानी जाएगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली जीत एक राज्य में सत्ता हासिल करने से अधिक उस आंदोलन की जीत मानी जाएगी जिसे आम आदमी ने सफल बनाके दिखाया था। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मत-भिन्नता होना बड़ी बात नहीं। किसी भी लोकतांत्रिक दल में मत-भिन्नता का होना उसकी ताकत का अहसास कराता है लेकिन इस मत-भिन्नता के टकराहट में बदलने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। पार्टी नेतृत्व अपने को नेता समझने की बजाय कार्यकर्ता समझें और मिल-बैठकर हल निकालें। साथ ही प्रयास ऐसे हों ताकि बंद कमरे की बात बाहर निकलकर बतंगड़ न बनने पाए।

> पार्टी जब अपने वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही हो, ऐसे समय में शीर्ष नेतृत्व में टकराहट आम आदमी के लिए पीड़ादायक मानी जाएगी।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। - वाल्तेयर

बात-करामात

नाकाम स्मारक

आपको हुई हो या नहीं पर हमें अपने प्रधानमंत्री मोदीजी की एक बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। लोकसभा में अपने जोरदार तेवरों के साथ उन्होंने फरमाया कि वे 'मनरेगा' को बंद नहीं करेंगे क्योंकि यह कांग्रेस की नाकामी का स्मारक है और बार-बार मनरेगा की विफलता का ढोल पीटते रहेंगे। खूब ढोल पीटो साहब। वैसे भी आप ढोल बखूबी बजा सकते हैं, यह तो आपने अपनी जापान यात्रा में बाकायदा सिद्ध कर ही दिया था लेकिन एक बात जरा हमारे जैसे मंदबुद्धि को भी समझा दीजिए कि अगर मनरेगा विफल है तो फिर आपके खजाना मंत्री जेटली काहे इस योजना के लिए बजट में बत्तीस हजार करोड़ रुपए खर्च करने प्रावधान कर रहे हैं। क्या सचमुच कांग्रेस की 'कब्र' खोदने के लिए इस देश की जनता के जेब से ऐंठा गई इतनी बड़ी रकम लुटाना ज्यादा जरूरी है। मनरेगा विफल है तो इसे बंद काहे नहीं कर देते। अजी जनता ने तो आपके झांसे में आकर कांग्रेस को तो पिछले साल ही चारों खाने चित कर दिया था। अब आपकी बातों से यही लग रहा है कि आप मनरेगा को इसलिए विफल करार दे रहे हैं क्योंकि यह कांग्रेस के जमाने में शुरू हुई है और इसे बंद करते ही ग्रामीण जनता आपको कोस सकती है। इस बात का दूसरा अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि आपको अपने बदनाम होने की चिन्ता है चाहे उसकी कीमत बत्तीस हजार करोड़ रुपए ही क्यों न हो। जहां तक हमें याद आता है नेता ऐसी भाषा लगातार बोलते रहे हैं। वे किसी अच्छे काम का श्रेय दूसरी पार्टी के नेताओं को देना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि यह 'सत्कर्म' कांग्रेस ने नहीं किया हो। वे भी अपने प्रतिद्वंद्वियों की अच्छी योजनाओं को नाकारा बताती रही है लेकिन तब और अब में बड़ा अंतर आ गया है। तब तो पता ही नहीं चलता था और सरकार में बैठे लोग कूलड़ियों में गुड़ फोड़ लेते थे। अब तो 'गूगल बाबा' पर जाकर एक क्लिक मारिए सारा लेखा-जोखा पल भर में आंखों के सामने आ जाता है। माना कि मोदी अच्छे वक्ता हैं लेकिन लोकसभा में जैसे व्यंग्य बाण आपने छोड़े और जिस हिकारत से विपक्ष को गरियाया वैसा तो आपके यशस्वी प्रधानमंत्री अटल जी तक ने कभी नहीं किया था। उस कठिन वक्त में भी नहीं जब मात्र एक वोट से उनकी सत्ता चली गई थी। सच तो ये है कि मनरेगा ही नहीं आम जनता के लिए लोकतंत्र के नाकाम स्मारक तो हरेक सत्ताधारी दल में हैं। कोई अपने को कितना भी दूध का धुला कहे लेकिन सत्ता की गलियों में उड़े नाकामी और धांधलियों के छींटे उनके और उनकी पार्टियों के दामन पर साफ नजर आते हैं। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री मानी जाती रही है पर भाजपा में कितने और कैसे-कैसे भ्रष्टाचारी हुए हैं इसका हिसाब आम आदमी खूब जानता है। अगर सचमुच मनरेगा एक नष्ट स्मारक है तो कृपया इसे बंद करके हमारे जैसे मुफलिसों को टैक्स में थोड़ी छूट ही दिला देते। घरवाली को एक आध सस्ती साड़ी दिलाकर वाहवाही लूट लेते। आपने तो इनकम टैक्स में एक रुपए की भी छूट नहीं दी।

– राही

> कोई अपने को कितना भी दूध का धुला कहे लेकिन नाकामी और धांधलियों के छींटे उनके दामन पर साफ नजर आते हैं

प्रत्यक्ष : जिज्ञासा

महासमर 2358

'कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मथुरा के समान यहां भी किसी प्रकार की रथ-संचालन-स्पर्द्धा रखना चाहते हैं?' 'नहीं! ऐसा कुछ तो नहीं है।' कृष्ण बोले, 'आप जानते हैं हस्तिनापुर में दुर्योधन और उसके दुष्ट मंत्री भी हैं। मुझे उनसे अपनी रक्षा के लिए सैनिक तो चाहिए ही।' 'पर सैनिक तो उपप्लव्य में पर्याप्त हैं। आपने जितने लोग द्वारका से बुलाए हैं, हम इससे भी दुगने सैनिक आपको यहां से दे सकते थे।' 'जानता हूं।' कृष्ण मुस्कराए, 'पर मुझे तो द्वारका के ही सैनिक चाहिए।'

'क्यों? क्या हमारे सैनिकों पर विश्वास नहीं है आपको?' 'मुझे है, किंतु संभव है कि द्वारका के यादवों को न हो।'

युधिष्ठिर कुछ समझे, कुछ नहीं समझे किंतु इतना तो समझ ही गए कि कृष्ण के मन में कोई विशिष्ट योजना थी। वे युद्ध करने नहीं जा रहे किंतु प्रहारक शक्ति अपने साथ रखना चाहते थे, चाहे वह प्रदर्शन के लिए ही हो। अनेक अवसरों पर शक्ति-प्रदर्शन की भी आवश्यकता होती है। उन्हें उपप्लव्य के सैनिकों पर विश्वास है किंतु वे अपने साथ उन सैनिकों को ले जा रहे हैं जिन पर द्वारका के यादवों को भी विश्वास है। उन्हें शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं है किंतु वे तीव्रगामी दल चाहते हैं। कृष्ण अभी नहीं बताएंगे कि वे क्या करना चाहते हैं। वे किस बात की तैयारी कर रहे हैं। वे प्रहार करेंगे अथवा प्रतिरोध? क्या चाहते हैं कृष्ण? युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा नहीं और कृष्ण ने बताया नहीं। सब जानते थे कि कल प्रातः कृष्ण हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करेंगे। इससे अधिक कुछ नहीं।

***

रात्रि के भोजन के पश्चात् पांचों पांडव युधिष्ठिर के भवन में एकत्रित थे। द्रौपदी, सुभद्रा, देविका, बलंधरा, करेणुमती और विजया भी वहां उपस्थित थीं। अर्जुन को यह देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि उद्धव, कृतवर्मा और सात्यकि भी वहां उपस्थित थे। एक नहीं थे तो कृष्ण ही नहीं थे। 'कृष्ण कहां हैं?' अर्जुन ने पूछा। उसने किसी को संबोधित नहीं किया था किंतु जिस प्रकार वह उद्धव की ओर देख रहा था, उससे स्पष्ट था कि उत्तर की अपेक्षा भी उद्धव से ही थी।

'मैं नहीं जानता।' उद्धव ने कहा, 'संभवतः कोई भी नहीं जानता। हो सकता है कि वे इस समय अपने उन अश्वों की सेवा कर रहे हों जिन्हें कल प्रातः रथों में जुतना है। यह भी संभव है कि वे उपप्लव्य से योजनों दूर किसी वन में अपने साथ जाने वाले सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे हों। और यह भी संभव है कि वे किसी संन्यासी की कुटिया में बैठे उससे ब्रह्म विद्या, ईश्वर और जीवन के संबंध में कोई जिज्ञासा कर रहे हों।'

'संभव तो यह भी है कि सब कुछ भूलकर वे किसी एकांत स्थान में ध्यान लगाए बैठे हों।' कृतवर्मा ने कहा।

'मुझे आश्चर्य है कि श्रीकृष्ण ने तुम लोगों को द्वारका से बुला भेजा और हम से उसकी चर्चा भी नहीं की।' युधिष्ठिर बोले। 'स्पष्ट है कि वे आप में से किसी को अपने साथ हस्तिनापुर नहीं ले जाना चाहते।' सात्यकि ने उत्तर दिया।

'वह तो स्पष्ट है ही।' अर्जुन ने कहा, 'किंतु यदि उन्हें अपने साथ सहायक रखने ही थे तो उन्होंने बलराम भैया को क्यों नहीं बुलाया।'

क्रमशः

– नरेन्द्र कोहली

आम बजट : प्रधानमंत्री ने की थी आलोचना फिर भी बढ़ाया गया आवंटन

मनरेगा पर दुविधा भारी

मनरेगा के लिए बजट आवंटन पिछले साल से भी अधिक किया गया है। यह वही योजना है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही संसद में 'गड्ढे भरने का काम' करार देकर उपहास उड़ाया था। जिस योजना को प्रधानमंत्री खुद ही अनुपयोगी मानते हों उस योजना को ही इतने भारी-भरकम बजट आवंटन के औचित्य को किस तरह से समझा जाए ? क्या प्रधानमंत्री मनरेगा की आलोचना सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि वह पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू की थी या फिर सरकार में इतना राजनीतिक साहस नहीं रहा कि वह एक गलत योजना को खारिज कर सके और उसकी जगह किन्हीं बेहतर और उपयोगी योजनाओं में यह पैसा लगाए। क्या है हकीकत, पढ़िए आज के स्पॉटलाइट में जानकारों की राय :

आवंटित राशि

वर्ष	राशि (करोड़ में)
2015-16	34,699
2014-15	33,353
2014-15	34,000 (अंतरिम बजट)
2013-14	33,000
2012-13	30,274
2011-12	29,213

10.75 करोड़ लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं मनरेगा के तहत

आजादी के 60 साल बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। मनरेगा आपकी (कांग्रेस) विफलताओं का स्मारक है। **-नरेंद्र मोदी,** प्रधानमंत्री

राजनीतिक साहस नहीं रहा सरकार में

पार्थ जे शाह
सेंटर फॉर सिविल सोसायटी

> मनरेगा को जारी रखने की जरूरत नहीं थी। मनरेगा को बजट में 30 हजार करोड़ से अधिक का जो आवंटन किया गया है वह बुनियादी सुविधा के निर्माण पर हो सकता था।

दिल्ली में भाजपा की हार के बाद मोदी सरकार राजनीतिक साहस की कमी से जूझ रही है। इसलिए सरकार में यह साहस नहीं रहा कि वह मनरेगा जैसी नाकाम रोजगार योजनाओं को बंद कर सके। भाजपा को डर है कि अगर उसने इस तरह की योजनाओं को बंद किया तो उन्हें गरीब विरोधी करार दे दिया जाएगा। दिल्ली की हार से भाजपा ने यह बिल्कुल गलत निष्कर्ष निकाल लिया है। दिल्ली में भाजपा की हार का कारण यह कतई नहीं रहा है कि आप पार्टी ने दिल्ली में फ्री बिजली और पानी देने का वायदा किया था। हकीकत यह है कि भाजपा को दिल्ली में उच्च, मध्यम और निम्न तीनों ही वर्ग में आप से कम वोट मिले हैं। यह सिर्फ फ्री बिजली या पानी के वादों के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उच्च और मध्यम वर्ग को इसका फायदा नहीं मिला है। सच यह है कि 9 माह के कार्यकाल में भाजपा ने अपने चुनावी वायदों जैसे भ्रष्टाचार, काले धन और रोजगार सर्जन की दिशा में कुछ नहीं किया था। मई 2014 के बाद से कई विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ऐसा लगने लगा था कि उनमें भी कांग्रेस की तरह अहंकार आ गया है। इसलिए दिल्ली के लोगों ने भाजपा को सबक सिखाने के लिए आप को वोट दिया है, जिससे भाजपा से लड़ने के लिए भी कोई पार्टी रहे।

मनरेगा को जारी रखने की कतई जरूरत नहीं थी। मनरेगा को 30 हजार करोड़ से अधिक बजट का जो आवंटन किया गया है वह किसानों के कृषि प्रशिक्षण, सड़क निर्माण, सिंचाई सुविधाओं और स्वच्छ भारत अभियान के टॉयलेट आदि के निर्माण लिए किया जाता तो बेहतर होता। आखिर इन कामों के लिए भी तो लोगों को रोजगार दिया ही जाएगा। अभी मनरेगा में जो काम होता है उससे किसी स्थाई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। मनरेगा में अधिक से अधिक लोगों को काम दिए जाने के उद्देश्य से यह प्रावधान जोड़ा गया है कि इस योजना के अंतर्गत भारी मशीन और महंगी निर्माण सामग्री आदि का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मिट्टी, पत्थर आदि से ही निर्माण कार्य किया जाता है। इसलिए मनरेगा में अगर कोई सड़क बनती भी है तो वह एक ही बारिश में धुल जाती है। किसी भी स्थाई बुनियादी ढांचे जैसे पक्की सड़क, नहर आदि खोदने का काम इसमें नहीं होता और निम्न गुणवत्ता वाली परिसपंत्तियों को निर्माण ही इसमें होता है। इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार अब भी परिवर्तन तो कर सकती है पर इसमें वह राजनीतिक साहस नहीं बचा है। सरकार को लगता है कि अगर वह ऐसा कुछ करेगी तो उसे गरीब विरोधी समझ लिया जाएगा। बजट के बाद सरकार पर ऐसे आरोप पहले ही लग चुके हैं कि सारा पैसा कॉर्पोरेट के पास जा रहा है।

मनरेगा की दूसरी खामी है कि यह उस योजना से भी खराब है जिसकी नकल के आधार पर यह बनाई गई। महाराष्ट्र में 1970 से एक 'रोजगार गारंटी योजना' चली आ रही थी जो कि मनरेगा लागू होने के बाद बंद हुई है। इस योजना के अंतर्गत हर उस जरूरतमंद को सिर्फ 100 दिन नहीं, सालभर काम देने का प्रावधान था, जो कोई भी सरकार के पास काम मांगने जाता था। पर इसमें एक ही शर्त थी कि इसमें मजदूरी बाजार भाव से कम रखी गई थी। यह भी एक तरह की सब्सिडी ही थी, पर इस तरह की योजनाओं को 'क्लीन सब्सिडी' कहा जाता है। क्योंकि इसमें अपने आप ही सिर्फ जरूरतमंद ही काम मांगने आते थे। इसमें काम करने वाले श्रमिक बाजार में बेहतर मजदूरी की तलाश भी करते रहते थे। जैसे ही उनको बाजार में अच्छी मजदूरी मिल जाती, वे यहां काम छोड़ देते। जबकि काम की गारंटी कानून से पोषित हो रही मनरेगा योजना हकीकत में न तो काम की गारंटी सुनिश्चित करती है (सिर्फ 100 दिन काम की गांरटी है) और न ही वर्ष भर न्यूनतम आय का सहारा ही बन सकती है। न्यूनतम मजदूरी बाजार से ज्यादा निश्चित करने और कानूनन काम की गारंटी का अधिकार दिए जाने से मनरेगा में काम पा सकने वाले अब बाजार में काम ढूंढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। जबकि इन लोगों को 100 दिन के बाद काम से हटाया जाता है, जो कि पुरानी स्कीम में नहीं होता था। साथ ही, पुरानी स्कीम में जो निर्माण कार्य होते थे वो भी स्थाई होते थे। इसलिए मनरेगा को वर्तमान रूप में जारी रखने का औचित्य नहीं है।

क्यों फैलाएं हाथ...

सोमपाल शास्त्री, पूर्व कृषि मंत्री

एक ओर प्रधानमंत्री द्वारा संसद में मनरेगा पर कटाक्ष करना और दूसरी ओर वित्त मंत्री द्वारा बजट में उसी योजना के लिए आवंटन बढ़ाना राजनीतिक दोगलापन दर्शाता है। नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के पहले भी इस योजना पर कटाक्ष करते थे और सत्ता में आने के बाद भी वह यही बात कह रहे हैं। उन्होंने संसद में कहा कि मैं मनरेगा को इसलिए जीवित रखना चाहता हूं क्योंकि यह कांग्रेस की समाप्ति का प्रतीक है। अब सवाल है कि फिर मोदी इसे अपना प्रतीक क्यों बनाए रखना चाहते हैं? दरअसल, जब यह योजना बनी थी, तभी से भ्रष्टाचार की आशंकाएं प्रकट होने लग गई थीं। माना जाता है कि मनरेगा के लिए आवंटित राशि का 30 फीसदी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि इस योजना से गरीबी हटाने में कितनी मदद मिलती है या मिलती ही नहीं है?

एक सर्वमान्य तथ्य यह है कि मनरेगा सरीखी नकद राशि प्रदान करने वाली योजनाएं न केवल प्रशासनिक स्तर पर दुरुपयोग का शिकार होती हैं बल्कि जिस परिवार को नकद धनराशि मिलती है, वहां भी इसका दुरुपयोग होता है। भारत में कई क्षेत्रों में मनरेगा में पुरूष की बजाय महिलाएं काम करती हैं और उससे होने वाली आय को पुरूष नशे आदि में खर्च कर देते हैं। इस योजना की अनिवार्यता भी है कि परिवार के किसी भी वयस्क को काम देना होता है, भले ही वह शराबी हो, नशेड़ी हो। मनरेगा के पीछे भावना यह थी कि इसका उपयोग उत्पादक सम्पत्ति निर्माण में होगा पर देखा यह गया है कि लोग केवल मिट्टी उठा रहे हैं। कई जगह अनपढ़ लोगों के अंगूठे के निशान लेकर उनकी मजदूरी हड़पी जा रही है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि मनरेगा के बाद ग्रामीण इलाकों में दैनिक मजदूरी बढ़ी है और गरीबों को आंशिक लाभ भी हुआ है। पर रोजगार के बारे में एक शाश्वत नियम यह है कि ऐसा रोजगार दिया जाए, जो उत्पादक हो और उससे अर्जित आय से व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़े और वह सम्मानपूर्वक अपना जीवन चला सके। इस पर मनरेगा खरी नहीं उतरती है। इसमें लोगों को सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि भीख की तरह भी है। इससे गरीबी का स्थायी निदान नहीं होता है।

> सर्वमान्य तथ्य यह है कि मनरेगा सरीखी नकद राशि प्रदान करने वाली योजनाएं न केवल प्रशासनिक स्तर पर दुरुपयोग का शिकार होती हैं बल्कि जिस परिवार को नकद धनराशि मिलती है, वहां भी इसका दुरुपयोग होता है।

गरीबी का स्थायी निदान

जिन ग्रामीण इलाकों में केवल बारिश से ही सिंचाई होती है, वहां अगर सरकार सिंचाई का प्रबंधन कर दे तो उस भूमि का उत्पादन बढ़ सकता है। इससे गरीबी का एक स्थायी निदान भी होगा। मनरेगा में दिया जाने वाला पैसा वैकल्पिक तौर पर जल संधारण या जलग्रहण योजना में लगाया जाए तो बेहतर होगा। भारत की 82 फीसदी ग्रामीण आबादी में से 60 फीसदी बिना सिंचाई की सुविधा में रहता है।

इन क्षेत्रों की गरीबी हटाने के लिए मनरेगा के 34 हजार करोड़ रुपए सिंचाई सुविधा में लगा दिए जाएं तो वहां कृषि उत्पादकता 1.1 टन प्रति हैक्टेयर से बढ़कर चार टन प्रति हैक्टेयर हो सकती है। इससे गरीबी, कुपोषण का स्थायी निदान होगा। लोग अपनी क्रयशक्ति का अधिकारपूर्वक इस्तेमाल कर सकेंगे। जब तक लोग सरकार के आगे हाथ फैलाते रहे तब तक वे सम्मान से नहीं जी सकते। मनरेगा जैसी योजनाओं से होने वाला भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। मोदी मनरेगा के खर्च का उत्पादक लाभ सुनिश्चित करें और गरीबी के निदान की ओर काम करें। गरीबों को सरकारी शिकंजे से छुटकारा मिले।

रोजगार योजना तो चाहिए

प्रो. अभिजीत सेन
पूर्व सदस्य, योजना आयोग

भारत में पिछले तीस-चालीस वर्ष से कोई न कोई रोजगार योजना चलती रही है। वह चाहे जवाहर रोजगार योजना हो, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना हो या फिर मनरेगा जैसी योजना जो कि यूपीए सरकार ने शुरू की थी। मोदी सरकार ने भी मनरेगा को बंद नहीं किया है। इसी से यह जाहिर है कि सरकार इसकी जरूरत तो महसूस कर रही है। वह जरूरत राजनीतिक भी हो सकती है। लेकिन गरीबों के लिए काम की गारंटी देने वाली कोई योजना हो, इसकी जरूरत देश में है। जहां तक मनरेगा में अधिक बजट आवंटन की बात है तो वाजपेयी की एनडीए सरकार के दौरान जो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना चलती थी उसमें बजट का आवंटन जीडीपी के अनुपात की तुलना में 0.4 प्रतिशत था। यह आवंटन वर्तमान में मनरेगा को जीडीपी के अनुपात की तुलना में 0.27 प्रतिशत आवंटन से अधिक है। पर इस योजना का वो असर नहीं दिखा था जो कि मनरेगा का हुआ। मनरेगा एक बेहतर योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई योजना है। सरकार की सभी रोजगार योजनाओं की तरह गड़बड़िया इसमें भी हैं। एक कमी तो यही है इसमें बहुत अच्छी परिसपंत्तियों का निर्माण नहीं हो सकता। इस दिशा में योजना में जरूरी परिवर्तन किए जाने चाहिए। पर हमारे देश में रोजगार योजना की जरूरत से इंकार नहीं किया जा सकता।

राजनीतिक लागत की चिंता

प्रो. अंशुमान गुप्ता

मनरेगा की सबसे बड़ी कमी यह रही है कि उसमें जो काम होते थे वो बहुत उत्पादक नहीं हुए। इसलिए मनरेगा की आलोचना होती रही है। अभी सरकार ने मनरेगा के लिए सिर्फ बजट आवंटन ही किया है। बजट के बाद भाजपा की ओर से जो बयान आए हैं उससे यह लगता है कि वह योजना के क्रियान्वयन में कुछ परिवर्तन भी करना चाहती है। बजट में क्रियान्वयन संबंधी पहलू उजागर किए जाएं यह जरूरी भी नहीं होता। पर यह सच है कि राजनीतिक रूप से मनरेगा जैसी योजना को हटाना एकदम संभव नहीं है। भारत में किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं के अभाव में इस तरह की योजनाएं वंचित तबके को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती हैं। इसलिए मनरेगा को खत्म करने से सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगेगा। भाजपा को इसी वर्ष बिहार में चुनाव लड़ना है। इसके अलावा राज्यसभा में भी सरकार के पास बहुमत नहीं है। वहां सरकार अन्य दलों के समर्थन पर आश्रित है।

बांग्लादेश के अखबार से...

विपक्ष का तेज हथियार अवरोध और हड़ताल

कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए नित नए अवरोध खड़े करना और लंबी हड़ताल विपक्षी गठबंधन का सबसे बड़ा हथियार है। बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाले 20 दलों के गठबंधन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शेख हसीना वाजेद की अवामी लीग सरकार की नाक में दम कर रखा है। डेढ़ महीने से ज्यादा समय से चल रही हड़ताल से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और लोगों की रोजमर्रे की जिंदगी भी ठहर सी गई। सालाना परीक्षाओं में नहीं बैठ पाने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। अनेक बड़े शहरों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की वारदातों से आंदोलनकारियों का पुलिस व सुरक्षा बलों से सीधा टकराव होने पर तनाव बढ़ने के आसार हैं। सरकार एहतियाती उपायों पर गौर कर रही है।

फोटो कॉर्नर

जिज्ञासा : धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु का संदेश सुन रहा एक उत्साही बालक।